loans granted in the context of militancy and the request of Jammy & Kashmir for write off of the State's outstanding liability on Government of India loans would also be considered.

(b) Orders have been issued regarding waiving of the repayment obligation on the balance unpaid instalments for the years 1997-98 to 1999-2000 in respect of the special term loans given to the State of Punjab during the years 1984-85 to 1993-94 for combating insurgency and militancy in the State. No order has been issued in the case of Jammu & Kashmir as the State receives special financial assistance to compensate for its non-plan deficit.

(c) North Eastern States already receive special assistance of various types to neutralise their specific financial burden arising out of militancy and other factors.

Extension of Ahmedabad Airport

*94. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT:
SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government has included the work of extension of Ahmedabad airport in the budget of financial year 1997-98;

(b) if not, what is the probable year; and

(c) by when actual work for development of Ahmedabad airport will start?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The detailed engineering and tender formalities of the project for the extension of runway to 11,500 ft. and associated works at an estimated cost of Rs. 48.50 crores shall be completed during the year 1997-98 and physical work will be taken up during the year 1998-99.

Tourists from Abroad

*95. DR. MANMOHAN SINGH: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) how does the trend of tourist arrivals from abroad in 1997-98 compare with the corresponding period in 1995-96 and 1996-97; and

(b) whether Government has drawn up any specific plan to promote tourism in the North-Eastern region; if so, what are the main features of this plan?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF TOURISM (SHRI SRIKANTA KUMAR JENA): (a) The international tourist arrival in India during the period April 1997 to October 1997 as compared to the corresponding period of previous two years are given below:—

Year (April-October)	Tourist Arrivals	%Change
1995-96	1076063	—
1996-97	1134070	5.4
1997-98	1164144	2.7

(b) A Task Force was set-up by the Department of Tourism to study the special problems of the North-Eastern region. The Task Force has recommended improvement of infrastructural facilities including air access, development of specific tourist destinations, human resource development and effective promotional efforts. The Task Force has also identified a number of projects for tourism development in the region and some of them have been prioritised for Central financial assistance during 1997-98.

दवाइयों की कीमतें

*96. **डा० महेश चन्द्र शर्मा:** क्या वित्त मंत्री 15 मई, 1997 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 4276 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवम्बर, 1997 में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को प्राप्त शिकायत के आधार

पर की गई प्रारंभिक जांच करने के बाद भी 12 मई, 1997 तक कोई कार्यवाही शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) ऐसी शिकायतों का निपटान करने के लिए आयोग को अधिकतम कितना समय लगता है;

(ग) क्या आयोग अपनी कार्यवाहियों को सार्वजनिक करता है तथा क्या शिकायतकर्ता को लम्बित शिकायत के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और की गई कार्यवाही के बारे में सूचित किया गया है;

(घ) 12 सितम्बर, 1997 को हुई सुनवाई के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) क्या शिकायतकर्ता को भी सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम):

(क) औषध उद्योग में व्याप्त कतिपय अनुचित व्यापार प्रथाओं के बारे में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एम आर टी पी सी) में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। एम आर टी पी आयोग ने शिकायत के प्राप्त होते ही जांच का आदेश दे दिया था। शिकायत की प्रारंभिक जांच निदेशक (अनुसंधान) एम आर टी पी आयोग, ने मार्च, 1992 में 11 कम्पनियों के विरुद्ध की थी। निदेशक (अनुसंधान), जिन्होंने जांच की थी, ने आंकड़ों के लिए कई पार्टियों से सम्पर्क किया और प्रारम्भिक जांच के लिए मामला तैयार किया और सितम्बर, 1993 में इसे आयोग को प्रस्तुत किया। आयोग ने यह नयायिक दृष्टिकोण अपनाया कि प्रत्येक मामले में अलग जांच रिपोर्ट की आवश्यकता होगी ताकि अन्य कम्पनियों के तथ्यों तथा आंकड़ों को, बाजार के गुप्त होने के कारण प्रतिस्पर्धिओं को प्रकट नहीं किया जा सके। इसमें कुछ समय लगा। एम आर टी पी विनियमन, 1991 के विनियमन 50 तथा 51 के साथ पठित धारा 10(क) (vi) के अन्तर्गत जांच के नोटिस का इश्यू न्यायिक कार्यवाहियों के भाग हैं। आयोग ने जांच के नोटिस के इश्यू को मार्च 1997 में न्यायिक दृष्टि से देखा। मामला आयोग द्वारा सुनवाई के अन्तर्गत है और मामला न्यायाधीन है।

(ख) आयोग के समक्ष कार्यवाहियां इन मामलों में न्यायालय की कार्यवाहियों की प्रकृति की हैं और इन मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

(ग) कार्यवाहियां खुले न्यायालय में की जाती हैं जहां जनता को आमतौर पर उपस्थित रहने की अनुमति दी जाती है। चूंकि आयोग के समक्ष यह मामला न्यायालय की कार्यवाहियों की प्रकृति का है अतः कोई भी सूचना आयोग के निर्देश पर ही दी जा सकती है। शिकायतकर्ता आयोग को इस उद्देश्य के लिए लिखित अनुरोध करने के बाद किसी भी समय फाइल का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है।

(घ) मामलों की अगली सुनवाई की तारीख 5.12.97 तय कर दी गई है।

(ङ) जब मामला सुनवाई के लिए आता है तो शिकायतकर्ता न्यायालय में उल्लेख कर सकता है या वह इस आशय का एक आवेदन फाइल कर सकता है और आयोग के निर्देशों को प्राप्त करने के बाद ही उसे सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है।

Ordinance amending the provisions of Prasar Bharati Legislation

*97. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the details of the factors, considerations and circumstances which prompted Government to issue an Ordinance late last month amending some provisions of the Prasar Bharati Legislation; and

(b) what is the justification, if any, for such a hurry?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. JAIPAL REDDY): (a) and (b) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 was brought into force w.e.f. the 15th September, 1997. However, the process of constitution of the Board of Prasar Bharati could not be immediately initiated as some of the provisions of the 1990 Act became outdated and redundant and some more concrete steps were required to be taken to augment the autonomy and enhance the efficacy of Prasar Bharati. Amendments were also required to remove the overlap between Prasar Bharati and Broadcasting Authority which is proposed to be put in place through a separate enactment. In view of the above, it was considered necessary to take immediate steps for amending the principal Act, and thus enabling the constitution of the Board.